>

Title: Need to expedite completion of Anandnagar-Ghughli by-pass over Mahrajganj rail line under Eastern Railways in Uttar Pradesh.

श्री हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उ.प्र.): चालू वर्ष में उत्तर प्रदेश में पूर्वोत्तर रेलवे अंतर्गत आनंदनगर-घुघली बरास्ता महाराजगंज रेल परियोजना अपडेट होकर 6.97 प्रतिशत प्रतिफल सर्वेक्षण रिपोर्ट को योजना आयोग ने सैद्धांतिक सहमति प्रदान करते समय प्रदेश सरकार से मुफ्त भूमि एवं निर्माण व्यय का 50 प्रतिशत वहन करने की शर्त रखी।

योजना आयोग ने नई रेल लाईन निर्माण हेतु यह नीति इसी वर्ष से प्रारंभ की है। देश के पिछड़े राज्यों द्वारा निर्माण व्यय का 50 प्रतिशत वहन करना एवं मुफ्त भूमि उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

ज्ञातव्य रहे कि स्वतंत्रता के पश्चात् देश में लगभग 10 हजार किलोमीटर के रेल लाईन निर्माण के सापेक्ष उत्तर प्रदेश में नाममात्र एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग 50 किलोमीटर रेल लाईन का ही निर्माण हुआ है और नई नीति इसे आगे भी उपेक्षित रखेगी।

सरकार का यह दायित्व है कि पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में बढ़ रहे चीन के प्रभाव के चलते नेपाल से सटे जनपद मुख्यालयों को राष्ट्रीय हित की सामरिक महत्ता की दृष्टि से उन्हें रेल से जोड़ने में प्राथमिकता बरते।

रेल संघीय विषय है परंतु नई नीति कालांतर में राज्यों को अपनी रेल चलाने का मार्ग प्रशस्त करेगी जिससे संघीय ढांचे पर प्रभाव पड़ेगा।

अतः मेरी मांग है कि उत्तर प्रदेश एवं विशेषकर पूर्वी उत्तर की रेल लाईन निर्माण में अब तक हुई उपेक्षा को दूर करने एवं राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से आनंदनगर-घुघली बरास्ता महाराजगंज रेल लाईन हेतु प्रदेश सरकार से व्यय एवं मुफ्त भूमि की शर्त को समाप्त कर तत्काल रेलवे बोर्ड निधि आवंटित कर कार्य शुरू करवाए।